LOK SABHA

Monday, May 8, 1978/Vaisakha 18, 1980 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBER SWORN

SHRI KAIHO (Outer Manipur)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में गन्ने की निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री

*1007. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की गन्ने की अधिकांश फसल 15 अप्रैल, 1978 तक खेतों में खड़ी रही तथा मिल और क्रशर मालिक इस गन्ने को पेरने में असमर्थ हैं जिसके परिणामस्वरूप किसान गन्ने को निम्नतम निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर बेचने के लिए विवश हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मिलों और क्रशरों द्वारा गन्ने की खपत के लिए तथा किसानों को उसका निर्धारित मूल्य दिलाने के लिए कोई उपाय किये हैं और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष में कितना गन्ना पैदा हुआ तथा 30 अप्रैल, 1978 तक किसानों के खेतों में कितना गन्ना खड़ा रहा ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) to (c). A statement showing the position is placed on the Table of the Sabha.

Statement

All India second estimate of sugarcane acreage in Uttar Pradesh for the season 1977-78 is placed at 1691.4 thousand hectares as against corresponding estimate of 1494 thousand hectares last season. No estimates are available with the Central Government regarding the extent of sugarcane crop still remaining unharvested in U.P. as on 15th April, 1978. The necessary information has been called for from the Government of U.P. and will be placed before the House when received.

2. The range of minimum price fixed for cane purchased by vacuum pan sugar factories in the State of U.P. is Rs. 8.50 to Rs. 11.00 per quintal. The State Government have advised prices of Rs. 13.50 and Rs. 12.50 per quintal for Western and Central and East U.P. respectively. The State Government have informed that all sugar factories are paying this State advised price.

3. With the approval of the Central Government, the Government of U.P. have also fixed the following cane

prices for 1977-78 season for khandsari units:

Region	Minimum price fixed
Western Region (comprising of Muzzaffarnagar, Dehradun, Saharanpur, Meerut, Bulandshahar and Ghaziabad Districts).	Rs. 9·30 per quintal
Aligarh District	Rs. 8·50 per quintal
Central Region (comprising of Nainital except Madehi factory area, Etah, Farukhabad, Moradabad, Bareilly except Bareilly Sugar Factory area, Pilibhit, Bijnor, Saharanpur, Rampur, Hardoi, Shahjahanpur, Sitapur, Lakhimpur Kheri and Farrukhabad districts.	Rs. 9·40 per quintal
Bareilly Sugar Factory area	Rs. 8·70 per quintal
M/s. Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Nadehi, Distt. Nainital.	Rs. 8·50 per quintal
Eastern Region (Comprising of Barabanki, Faizabad, Jaunpur, Varanasi, Basti, Gonda, Baharaich, Deoria, Gorakhpur Distts.).	Rs. 8·70 per quintal
Districts other than those specified	Rs. 8·70 per quintal

4. The State Government have informed that they are determined to see that the above prices are paid to cane-growers and that all khandsari units are paying this fixed price except 465 units, out of a total of 3890 licensed units, which have challenged the State Government's notification fixing these prices in the Supreme Court. Where complaints are received regarding payment of cane price at rates less than those fixed by the State Government the offending units are prosecuted by the State Government. Besides this, checking squads have also been set up for detecting such cases and prosecuting the offenders.

5. The following measures taken by the Union Government are also mainly with a view to enabling maximising of cane consumption and payment of remunerative cane prices:

1. Levy price for levy sugar purchased from factories has been raised with effect from 1st March, 1978 by Rs. 18.08 per quintal.

2. Action is being taken to enable sugar factories to obtain adequate credit facilities in view of the high level of production.

3. A scheme has been notified on 28th April, 1978 for giving a rebate in excise duty to encourage and enable factories to crush beyond 30th April, 1978.

4. Restrictions on export of gur have been removed.

5. Excise duty on khandsari sugar was reduced by 50 and 75 per cent respectively on sulphur and deshi khandsari with effect from 4th February, 1978.

6. The Food Corporation of India and the National Agricultural Cooperative Marketing Federation had purchased gur at a premium above the market price.

7. Stock limits of khandsari dealers have been enhanced.

8. Export of khandsari has been permitted.

6. As already stated, estimated of sugarcane acreage in U.P. during the current year is 1691.4 thousand hectares. The quantum of sugarcane that will remain in the fields of farmers is, however, difficult to be estimated as the bulk of the cane in this state is used by the decentralised sector of gur and khandsari. Despite a late start of crushing, sugar factories in U.P. alone are, however, estimated to have produced about 14.60 lakh tonnes of sugar as against corresponding production of 14.14 lakh tonnes last year. 80 sugar factories have been reported to be working in U.P. as on 30th April, 1978 (out of a total of 86) as against corresponding figure of 22 last season.

श्री अनन्त राम जायसवाल : मान्यवर, सरकार ने ऐक्साइज ड्यूटी मे छूट दे कर, लैवी मूल्य में बढ़ोत्तरी कर के और ऐक्सपोर्ट सब्सिडी दे कर करीब 1 अरब ६० का फ़ायदा मिल मालिकों को पहुंचाया है । लेकिन नतीजा इसका यह है कि जहां तक उपभोक्ताओं का सवाल है वे भी रो रहे हैं क्योंकि उनको चीनी महंगी पड़ रही है । मिल मालिकों के अनुसार 80 प्रतिशत मिलों को भी घाटा हो रहा है, और जहां तक किसानों का सम्बन्ध है उन्हें निर्धारित मूल्य गन्ने का मिल ही नही रहा है और खड़ा गन्ना वह फूंक रहे हैं । तो मतलब यह है कि आपकी कोई लांग टर्म इंटेगरेटेड पोलिसी नहीं है । तो क्या सरकार तुरन्त ऐसी पोलिसी बनाने पर विचार करेगी, और इसके लिये कोई कमेटी मुकर्रर करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मान्यवर, एक बात मैं बारबार स्पष्ट कर चुका हूं, पुनः कर देता हूं कि जहां तक ओपिन वैकुअम पैन फ़ैक्ट्रीज का सम्बन्ध है उनको जो निर्धारित मूल्य राज्य सरकारों ने निर्धारित किया है वह मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है । इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो ऐक्साइज ड्यूटी रिलीफ़ वगैरह दी गई है यह फ़ैक्ट्रीज को कोई उपहार नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें इसलिये दिया गया है कि खुले बाजार में चीनी का मूल्य बहुत ज्यादा गिर जाने के बावजूद भी वह गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य दे सकें ।

जहां तक नीति निर्धारण का प्रश्न है यह बात सही है कि जो नीतियां चलती रही है उन पर पुनः विचार की आवश्यकता है और वह विचार चल रहा है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : मिल-मालिक कह रहे है कि हमे नुकसान हो रहा है, दुनिया मे सब से ज्यादा चीनी उत्पादन का खर्चा हमारा है और किसान को उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है । मंत्री महोदय गन्ने में दिलचस्पी भी रखते हैं और काश्तकार भी हैं । उन को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की मिलें प्रायः जर्जर हो गई हैं जिन्हें "सिक" कहा जाता है । इस के आलावा किसी मिल का माडर्नाईजेशन नहीं हुआ हैं । क्या उनको माडर्नाइज करने के लिए सारी सिक मिलों को बिना मुआवजा दिये सरकारी अधिकार मे ले लिया जायेगा, उन्हें माडर्नाइज किया जायेगा और पब्लिक सैक्टर में नई माडर्न मिलें खोल कर चीनी के उत्पादन खर्च को कम करने पर विचार किया जायेगा ।

श्री भानु प्रताप सिंह : माडर्नाइजेशन के बारे में हम सोच रहे हैं । लेकिन जो सिक मिलें हमने ले ली हैं, उन की दशा मे कोई सुधार नहीं दिखाई दिया है । इस लिए उनको टेक-ओवर करना कोई इलाज नहीं है, बल्कि इसके लिए कोई और इलाज ढूंढना पड़ेगा और वे इलाज ढूंढे जा रहे हैं । अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई सुझाव देंगे, तो उन पर विचार किया जायेगा ।

श्री ब्रजभूषण तिवारी: क्या अगले साल के लिए गन्ने के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित की गई है, क्योंकि इस

वर्ष ही गन्ना इतना अधिक है कि वह पेरा नहीं जायेगा ? अगर इसी प्रकार की अनियोजित योजना गन्ने के उत्पादन के सम्बन्ध में चलाई गई, तो अगले साल फिर फ़सल के खड़े रहने, और न पेरे जाने, की काफ़ी सम्भावना है । इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह बात सच है कि अगर गन्ने का रकबा न घटाया गया, तो जो स्थिति इस वर्ष है, वह अगले वर्ष भी जारी रहेगी, तकलीफ़ होगी, सरप्लस प्रोडक्शन होगा । इसलिए गन्ने की बुवाई के सम्बन्ध में रेडियो द्वारा और पर्चियों द्वारा किसानों को सावधान किया गया है कि वे गन्ने का रकबा घटा दें । मैंने इस सदन में और दूसरे सदन में भी कहा है कि अगर वे बो चुके हैं, तो वे उसे उखाड़ दें । गन्ना उत्पादकों के हितैषियों को चाहिए कि वे उन्हें मश्वरा दें कि वे गन्ने का रकबा कम करें और अपनी खेती को डाइवर्सिफ़ाई करें ।

Unidentified object in a Bottle of Milk of D.M.S.

+

*1008. DR. VASANT KUMAR PANDIT:

SHRI M. RAM GOPAL REDDY:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether an unidentified object was found in the milk bottle of Delhi Milk Scheme as reported in *Indian Express* dated the 11th April, 1978;

(b) whether any inquiry has been conducted into this; and

(c) if so, the result thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes Sir.

(b) and (c). Yes Sir; on verification of the contents of the bottle it was found that the unidentified object was a piece of wood.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Are you satisfied with the answer, Sir? The members are not satisfied with the answer. An investigation has been done and what looked like a cockroach or insect has been verified as wood. The entire milk scheme is automatic; no touch of human hand comes into it. Has the hon. Minister enquired into the fact as to how that piece of wood found its way into the bottle? That does not find a place in the answer.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I have thoroughly enquired into the whole issue. It is positively a piece of wood that has entered the bottle.

MR. SPEAKER: The question is, how it got into the bottle.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: For that, there are many stages. The bottles go from the milk plant for distribution. They can be tampered with or pilfered on the way also. The small cap, the aluminium cap, that is placed on the top can be tampered with and again replaced without identifying whether it has been tampered with. That is one stage. Subsequently, when the bottles go to our houses, there also some children or boys in the houses place some things like this.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Sir, is it possible?

MR. SPEAKER: Please allow him to proceed.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: It happens so many times. So, a child playing with the bottle can place a small stick or a small piece of wood or any other object in that. Then the bottles are collected and got there for washing etc. In this case it was found that this piece of wood could not be detected even at the time of washing. And then it has to go